



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

No. 46]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2006/चैत्र 3, 1928

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2006/CHAITRA 3, 1928

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2006

सं. 1-2/2006-बी एंड सीएस.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (के) के प्रावधान तथा धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा फाइल सं. 13-1/2004-रिस्ट्र से निर्गत अधिसूचना सं. 39 (एस.ओ. सं. 44 (ई) तथा 45 (ई) दिनांक 09/01/2004) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 36 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के पैराग्राफ (ii), (iii) तथा (iv) तथा उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

- i) यह आदेश "दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (पाँचवाँ संशोधन) आदेश, 2006 (2006 का 4)" कहा जाएगा।

(1)

(ii) यह आदेश संपूर्ण भारत में लागू होगा।

(iii) यह आदेश इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश 2006 (2006 का 2) के साथ पठित दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश 2004 (2004 का 6) में खण्ड 3क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के नीचे मौजूद दूसरे प्रावधान के बाद निम्नलिखित व्याख्या तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी:

**“व्याख्या 1:** उपर्युक्त 3क के प्रयोजन के लिए इस प्रश्न का निर्धारण कि क्या वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर, केबल ऑपरेटर अथवा एमएसओ अथवा ब्राडकास्टर को भुगतान करेंगे या नहीं, ब्राडकास्टर्स, एमएसओ (एमएसओएस), केबल ऑपरेटर (ऑपरेटर्स) के बीच हुए करार (करारों) की शर्तों के अनुसार अथवा ब्राडकास्टर (ब्राडकास्टर्स) और वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर (सब्सक्राइबर्स) के बीच अथवा एमएसओएस और ऐसे केबल ऑपरेटर्स, जिसे एक ओर वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स को और दूसरी ओर जैसा भी मामला हो, को सिगनल प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।”

3. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस आदेश के अनुबंध—क में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है।

आदेशानुसार,

राकेश कक्कड़, सलाहकार (बी एंड सीएस)

[विज्ञापन III/IV/142/2005/असा.]

**अनुबंध क****व्याख्यात्मक ज्ञापन**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने माननीय टीडीसैट की टिप्पणी और एफएचआरएआई के अभ्यावेदन के अनुसरण में यह उचित समझा कि अन्तरित अवधि में अधिकतम सीमा की सुरक्षा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी प्रदान की जाए। तदनुसार, प्राधिकरण ने 7.3.2006 को टैरिफ संशोधन आदेश (चौथा संशोधन आदेश) जारी किया। परन्तु वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स के मामले में गैर-वाणिज्यिक उपभोक्ता से भिन्न यह सुरक्षा, 1 मार्च, 2006 को विद्यमान दरों के स्तर पर उपलब्ध कराई गई है। यह भी इंगित किया गया था कि प्रस्तावित संशोधन अल्प अवधि उपाय है और विस्तृत जांच के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

2. विस्तृत जांच की दिशा में प्रारंभिक कदम के रूप में होटलों तथा ब्राडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुपों से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस प्रक्रिया के दौरान ब्राडकास्टर्स के ग्रुप ने एक अभ्यावेदन दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था:

"..... इस आदेश (7.3.2006 के टैरिफ संशोधन आदेश) से 17.1.2006 का आदेश (टीडीसैट का आदेश) निष्प्रभावी/उल्टा हो गया है (जोर देने के लिए इटैलिक्स में) टीडीसैट ने माना था कि होटलों को सेवाएं केवल प्राधिकृत तरीके से ही मुहैया कराई जानी चाहिए। अधिकांश होटल तथा वाणिज्यिक संस्थान ब्राडकास्टर्स से अपेक्षित प्राधिकार लिए बिना केबल ऑपरेटरों से सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। हमारे दृष्टिकोण में, वर्तमान व्यवस्था जिसके माध्यम से होटल और वाणिज्यिक संस्थान सफ्लाई प्राप्त कर रहे हैं, वह सिगनलों की पायरेसी के समान है। स्पष्ट खतरा, यह है कि

होटल/वाणिज्यिक संस्थाएं, ट्राई के टैरिफ आदेश का दुरुपयोग वर्तमान अप्राधिकृत व्यवस्था को सही करार देने के लिए करेंगे। होटल अथवा वाणिज्यिक संस्थापना को सेवा प्राप्त करने और उसके प्रदर्शन के लिए संबंधित ब्राडकास्टर से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। परन्तु, होटलों द्वारा खण्ड 43(क) का फायदा उठाकर निरन्तर सेवा प्राप्त की जा रही है और बिना किसी वैध लाइसेंस से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और एक अप्राधिकृत तरीके से.....  
.....।

3. 7.6.2006 के टैरिफ संशोधन आदेश के माध्यम से वाणिज्यिक केबल के उपभोक्ताओं को अधिकतम सीमा की सुरक्षा प्रदान करने के पीछे भाव तथा इरादा यह था कि उन वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर्स को भी सुरक्षा प्रदान की जाए जिन्हें टेलीविजन सिग्नल उनके द्वारा मुहैया किया जा रहा हो जो लिखित या मौखिक रूप से विधिवत् निष्पादित करारों के माध्यम से ऐसा करने के लिए प्राधिकृत हों। संशोधित आदेश के पीछे मंशा गैर कानूनी रूप से ब्राडकास्टिंग सेवाओं को बढ़ावा देने की नहीं थी।

4. माननीय टीडीसैट ने 17.1.2006 के अपने निर्णय के पैरा 37 में भी इसे माना है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है:

"..... अतः, हम प्रतिवादियों को यह अनुमति प्रदान करते हैं कि वे याचिकाकर्ताओं के एसोसिएशन तथा इसके सदस्यों के विरुद्ध, याचिकाकर्ताओं के एसोसिएशनों के सदस्यों द्वारा सिग्नल प्राप्त करने के कारण उनके देय विधिसम्मत रकम की वसूली के लिए कार्रवाई करें। यदि याचिकाकर्ताओं के एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रतिवादी ब्राडकास्टर्स के प्राधिकृत एजेंट/वितरक/एमएसओ को अभिदान का भुगतान किया है तो इसे विधि सम्मत भुगतान माना जाएगा परन्तु जहां कहीं ऐसा अभिदान अप्राधिकृत वितरक अथवा एमएसओ अथवा केबल ऑपरेटर्स को किया गया होगा तो ऐसे मामलों में प्रतिवादी ब्राडकास्टर्स के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वे याचिकाकर्ताओं के एसोसिएशन के सदस्यों से इस बारे में मांग करें....."

5. इसमें स्पष्टता लाने के लिए नए जोड़े गए खण्ड के वर्तमान दूसरे प्रावधान के नीचे व्याख्या जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2006

**No. 1-2/2006-B & CS.**—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) and Paragraphs (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 read with section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 and the Notification No.39 (S.O. No. 44(E) and 45 (E) dated 09/01/2004) issued from file No. 13-1/2004-Restg by the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub section (1) of Section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India, hereby makes the following Order:

**1. Short title, extent and commencement:**

- (i) This Order shall be called "The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fifth Amendment) Order 2006, (4 of 2006)"
- (ii) This Order shall apply throughout the territory of India:
- (iii) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2. In the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 (6 of 2004), read with the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fourth Amendment) Order 2006, (2 of 2006) after the existing 2<sup>nd</sup> proviso below clause 3A and the entries relating thereto, the following explanation and the entries relating thereto shall be added:

“Explanation 1: For the purpose of clause 3A above the question whether commercial cable subscriber will pay the cable operator/MSO/the broadcaster will be determined by the terms of agreement(s) between broadcasters, MSO(s), Cable Operator(s) or between Broadcaster(s) and the Commercial Cable Subscriber(s) or between MSO / Cable Operator

905 GI/06-2

who have been authorized to provide signals to the Commercial Cable subscriber(s), on the one hand, and Commercial Cable Subscriber(s), on the other, as the case may be”

3. Explanatory Memorandum:

This Order contains as Explanatory Memorandum attached as **Annex- A**.

By Order,

RAKESH KACKER, Advisor (B & CS)

[ADVT III/IV/142/2005/Ext.]

**Annex A**

**Explanatory Memorandum**

TRAI had in pursuance of the observations of Hon'ble TDSAT and the representation of FHRAI, considered appropriate, in the interim, to extend the protection of ceiling to the commercial consumers as well. Accordingly, the Authority issued a Tariff Amendment Order (Fourth Amendment Order) on 7.3.2006. This protection in respect of Commercial Cable Subscriber was however to be available at the level of the rates prevailing on 1<sup>st</sup> March 2006 unlike in the case of non-commercial consumer. The proposed amendment it was indicated to be a short-term measure and was to be reviewed on the basis of detailed examination.

2. As a part of initial step towards detailed examination a process of seeking inputs from groups representing hotels and broadcasters was initiated. During this process the group of broadcasters made a representation in which it was pointed out inter alia as under:

“.....The Order (*Tariff Amendment Order dated 7.3.2006*) has in effect nullified / reversed the order (*TDSAT order*) dated 17.1.2006. (emphasis in italics added). TDSAT recognized that the services to the hotels should be only through authorized means. A vast majority of the Hotels and Commercial establishments who obtain service through cable operators without requisite authorization from the broadcasters. In our view, the current arrangements through which Hotels and Commercial Establishments obtain supply is tantamount to piracy of signals. There is a

clear danger that Hotels /commercial Establishments shall misuse the TRAI Tariff Order to legitimize the present unauthorized arrangements. A hotel or a commercial establishment needs to obtain a license from the respective broadcaster to receive and exhibit the service. However, clause 4 3(A) is being exploited by the Hotels to continuously receive service and exhibit the services without a valid license and in an unauthorized manner...."

3. The spirit and intention behind the provision of extending the protection of ceiling to commercial cable consumers through the Tariff Amendment Order of 7.3.2006 was to cover those commercial cable subscribers who are provided television signals by those who are authorized to provide signals by virtue of agreements either written or oral. The intention of the amendment order is not to promote illegal provision of broadcasting services.

4. Hon' ble TDSAT in its judgment of 17.1.2206 has also recognized this in para 37 of the judgment wherein it has been indicated

".....Therefore, we leave upon the Respondents to proceed against the petitioners association and its members for recovery of legitimate amount due to them for receipt of signals by the members of petitioners associations. If the members of the petitioners association have paid the subscription to the authorized agent/distributor/MSO of the respondent broadcasters, then that will be treated as legitimate payment but wherever such subscription has been paid to unauthorized distributor or MSO or Cable operators it will be open to the respondent broadcasters to raise demands from the members of petitioners association....."

5. With a view to bring clarity to interpretation it has been decided to add an explanation below the existing 2<sup>nd</sup> Proviso to the newly added clause.